संपादकीय जागरण

बुधवार, 20 जून, 2018 : द्वि. ज्येष्ठ शुक्ल 8 वि. 2075

मनन करना मन का सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है

यह तो होना ही था

जम्मू-कश्मीर में पीडीपी-भाजपा सरकार जिस तरह चल रही थी उसके कारण एक अर्से से दोनों में अलगाव के आसार बढ़ते दिख रहे थे। बावजूद इसके भाजपा की ओर से पीडीपी से समर्थन वापस लेने का फैसला इसलिए अप्रत्याशित है, क्योंकि यह संघर्ष विराम की समाप्ति के तत्काल बाद लिया गया। इस फैसले से यही साबित होता है कि संघर्ष विराम के नतीजे अच्छे नहीं रहे। इसमें दोराय नहीं कि आतंकियों और उनके खुले-छिपे समर्थकों ने संघर्ष विराम का जवाब हिंसक तरीके से दिया, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि भाजपा ने केवल इसी कारण गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। यह गठबंधन इसलिए भी नहीं टूटा, क्योंकि यह बेमेल था, बल्कि इसलिए टूटा, क्योंकि पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार न तो कश्मीर की उम्मीदों पर खरा उतर पा रही थी और न ही जम्मू के। लद्दाख तो प्राथमिकता में दिखा ही नहीं। इस गठबंधन सरकार का एक बड़ा मकसद घाटी के हालात सामान्य करना और साथ ही जम्मू और कश्मीर के बीच की खाई को कम करना था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। उलटे जम्मू और कश्मीर के बीच की खाई बढ़ती दिखी। निःसंदेह इसकी एक बड़ी वजह मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रीति-नीति रही। इसी रीति-नीति के चलते गठबंधन के उस एजेंडे को ढंग से आगे नहीं बढ़ाया जा सका जिसे गहन मंथन के बाद तैयार किया गया था।

कहना कठिन है कि यदि मुफ्ती मुहम्मद सईद होते तो साझा सरकार का भविष्य क्या होता, लेकिन इसमें दोराय नहीं कि महबूबा मुफ्ती अनुकूल परिणाम न मिलने के बावजूद इस पर कुछ ज्यादा ही जोर देने की गलती करती रहीं कि पत्थरबाजों के प्रति नरमी बरती जाए और अलगाववादियों एवं पाकिस्तान परस्त तत्वों से बातचीत की पहल की जाए। एक हद तक ऐसा किया भी गया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही रहा। एक ओर कश्मीर आतंक एवं अराजकता के खुले समर्थकों के साथ-साथ पाकिस्तान की शातिर दखलंदाजी से त्रस्त बना रहा और दूसरी ओर जम्मू के हितों की अनदेखी भी होती रही। गठबंधन को बनाए रखने के लिए भाजपा को कदम-कदम पर समझौते ही नहीं करने पड़े, बल्कि अपने घोषित एजेंडे से पीछे भी हटना पड़ा। गठबंधन हित में उसने धारा 370 हटाने की अपनी मुहिम को तो स्थगित किया ही, कश्मीरी पंडितों की वापसी पर ज्यादा जोर भी नहीं दिया। इसके बदले उसे कुछ हाथ लगता नहीं दिख रहा था और समय बीतता जा रहा था। ऐसे में इस पर विचार करना ही था कि आखिर देश को और खुद उसे इस सरकार से हासिल क्या हो रहा है? चूंकि जम्मू संभाग के लोगों में यह भाव गहराता जा रहा था कि उनकी अनदेखी हो रही है इसलिए भाजपा के लिए इस गठबंधन को बनाए रखना मुश्किल हो गया था। यदि भाजपा भिन्न विचाराधारा वाली पीडीपी से अलग होने का फैसला करने में और देर करती तो शायद वह जम्मू में अपनी राजनीतिक पूंजी भी गंवा बैठती। गठबंधन सरकार का सफर असमय खत्म होने के बाद केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर में मन मुताबिक फैसले लेने में आसानी अवश्य होगी, लेकिन यह तय है कि सामान्य तौर-तरीकों से बात नहीं बनने वाली।

भर्ती परीक्षा घपला

चाहे जितनी सावधानी बरती जाए, हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंध लग ही जाती है। ताजा उदाहरण सिपाही भर्ती परीक्षा का है। पैसे लेकर नकल कराने वाला गिरोह इस बार भी इस भर्ती में खूब सक्रिय रहा। पुलिस भी सख्त थी और इसीलिए अलग-अलग जिलों में सॉल्वर गैंग के कई सदस्य पकड़े जा सके। पता चला सारे सॉल्वर बिहार से बुलाए गए थे। गिरोह का सरगना गोरखपुर का है। उसने चार से आठ लाख रुपये लेकर पास कराने का ठेका लिया था। अत्याधुनिक संसाधनों के जरिये गिरोह चला रहे लोगों की भनक पुलिस को लग गई और उसने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी।

याद कीजिए, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले को। सालों पहले हुए डॉक्टर भर्ती घोटाले के आरोपित आज तक गिरफ्तार किए जा रहे हैं। गत सोमवार को ही मप्र पुलिस इलाहाबाद से दो मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार कर ले गई। उस भर्ती घोटाले में उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे अनेक छात्रों ने सॉल्वर बनकर परीक्षा पास कराने का ठेका लिया था। बदले में उन्हें अच्छी रकम मिली थी। इनमें ज्यादातर छात्र उप्र के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक थे, पर जैसे-जैसे व्यापम घोटाले की परतें खुलती गईं, ये लोग गिरफ्तार होते चले गए। पढ़ाई के दौरान ही पैसे कमाने की ललक ने छात्रों का पूरा करियर चौपट कर दिया। दोष केवल लालच में आए छात्रों का ही नहीं है। असल अपराधी वे हैं जो परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाने में सफल हो जाते हैं। जरूरत उन्हें और उनके प्रभावशाली संरक्षकों को थामने की है।

असल अपराधी वे हैं जो परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाने में सफल हो जाते हैं। जरूरत उन्हें और उनके प्रभावशाली संरक्षकों को थामने की है

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या दिल्ली के उपराज्यपाल के यहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धरना देना सही है?

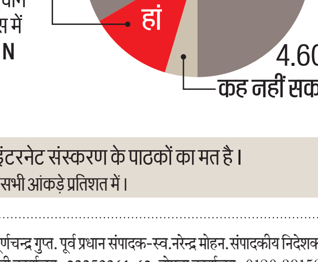

आज का सवाल

क्या भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में पीडीपी से समर्थन वापस लेकर सही किया है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

याद रहे सेक्युलर संविधान

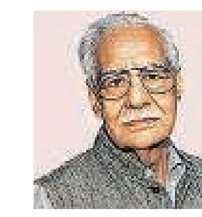

कुलदीप नैयर

यह जानते हुए भी कि मेरा दर्शन भाजपा के दर्शन के विपरीत है, मेरे घर आए अमित शाह ने मेरा संदेह दूर करने की कोशिश की

मैंने यह महसूस किया कि सेक्युलर विचारधारा मानने वाले भी दूसरों की ही तरह कट्टरपंथी हैं। पिछले दिनों भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के मेरे घर आने को लेकर काफी गुस्सा जाहिर किया गया। टेलीफोन और ई-मेल के जरिये तमाम आलोचना सुनने-पढ़ने को मिली। कुल मिलाकर सबका यही कहना था कि आपको उन्हें अपने घर आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इन आपत्तियों पर मैं अपनी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अमित शाह के आने के कुछ दिनों पहले कुछ कार्यकर्ता मेरे घर आए थे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय जेल में हम लोग साथ-साथ थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि अमित शाह के मेरे घर आकर मिलने से मुझे कोई एतराज तो नहीं होगा? मैंने उनसे कहा कि कोई भी मेरे घर आ सकता है और मैं विचारधारा के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करता। मुझे लगता है कि धर्म को राजनीति में नहीं मिलाने की मेरी विचारधारा सबसे अच्छी है और हमें इसे अपनी सीने पर बिल्ला लगाकर नहीं घूमना चाहिए। किसी को अपने विचार उन लोगों के सामने रखने से नहीं डरना चाहिए जो आपके सख्त खिलाफ हैं। वैचारिक मतभेद को बीच में नहीं आने देना चाहिए। आखिरकार, लोकतंत्र के मायने चर्चा और बहस ही तो है।

महात्मा गांधी ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत की थी और यहां तक कि बंटवारे पर जोर नहीं देने के लिए उन्हें राजी करने उनके घर भी गए थे। जब उन्हें लगा कि वह जिन्ना को मनाने में विफल हो गए तो भी उनके बीच विचार की कटुता नहीं थी। वास्तव में जिन्ना को राजी करने में असफल रहने के बाद गांधी जी 21 दिनों के उपवास पर चले गए थे। इसे उन्होंने 'शुद्धि' कहा था। इससे यही सीख मिलती है कि हमें अपने मतभेद दूर करने के लिए बैठकर बातचीत करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए।

मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि अमित शाह के बारे में मेरा विचार यही थी कि वह आग उगलने जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी शिष्टता और नम्रता, स्पष्ट विचार पद्धति, समझ, और सबसे ज्यादा अपने मिलनसार स्वभाव से मुझे चकित कर दिया। यह जानते हुए भी कि मेरा दर्शन उनके और भाजपा के दर्शन के विपरीत है, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बताया कि वह छह साल के थे जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना शुरू किया था। यह कहते समय उनकी आंखों में मैंने गर्व का भाव देखा। बेशक वह नागपुर की रगड़ खा चुके हैं। अमित शाह के लिए यह लंबी दौड़ थी, लेकिन अंत में वह पार्टी के अध्यक्ष पद तक पहुंच गए।

आज भारत एक चौराहे पर खड़ा है। हिंदुत्व को मानने वाले सत्ता को हथियाना चाहते हैं और धर्म को बीच में लाए बिना सबके एक रहने के सिद्धांत को बाहर फेंक देना चाहते हैं। मैंने अमित शाह के साथ बातचीत में इस विषय के कुछ हिस्से को छुआ। उन्होंने कहा कि जब भाजपा सत्ता हासिल करती है तो हर क्षेत्र को समग्र तरीके से विकसित करती है। मेरी राय थी कि इस प्रक्रिया में तो मस्जिद भी ढहा दी जाती है। इस पर वह उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास वहां के अफसरों पर निर्भर करता है। जिन दो बिंदुओं पर अमित शाह ने अपने विचार रखे वे थे-जाति और देश का विभाजन। उन्होंने कहा कि समाजवादी नेता जातीय राजनीति करते रह गए। उन्होंने समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया का नाम लिया और कहा कि वह हर वक्त जाति की बात करते थे। शायद यही कारण था कि शुरू के वर्षों में समाजवादी सिर्फ राज्यों में ही सत्ता हासिल कर पाए, केंद्र में नहीं। भाजपा अध्यक्ष ने इस पर जोर दिया कि मौजूदा दौर के समाजवादी नेता भी उसी राह पर चल रहे हैं।

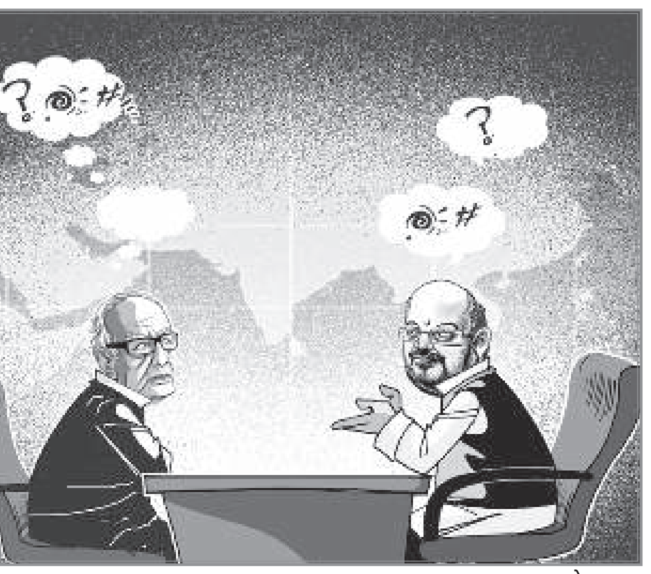

अवधेश राजपूत

यह अचरज की बात है कि सभी के विकास की राजनीति करने वाले जब सत्ता में आते हैं तो कुछ समूहों की बेहतरी को लेकर बंट जाते हैं। राज्य के स्तर पर तो इसे समझा जा सकता है, लेकिन वे केंद्र की सत्ता में आने पर भी विभाजन की राजनीति पर काबू नहीं रख पाते। सत्ताधारी भाजपा इसका उदाहरण है। उनके शासन के तहत करीब 20 राज्य हैं। भाजपा ने अलग-अलग राज्यों में सत्ता पाने के लिए अलग-अलग रणनीति एवं तरीके अपनाए हैं। हालांकि सेक्युलर विचारों वाली कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन अब वह वैसा संगठन नहीं रह गई है जैसा पहले कभी हुआ करती थी। 2019 में राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में होंगे तो कठिनाई महसूस करेंगे। मोदी ने भाजपा को विंध्य के पार पहुंचाने में सफलता पाई है। कर्नाटक का उदाहरण देश के सामने है।

देश के बंटवारे के बारे में अमित शाह ने कहा कि अगर हम लोगों ने इंतजार किया होता तो भारतीय उपमहाद्वीप का बंटवारा नहीं हुआ होता। इस मुद्दे पर वह गलत हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लार्ड क्लेमेंट एटली, जिन्होंने अपने शासन के अंत की घोषणा की थी, ने 6 जून 1948 का दिन तय किया था जब वह एक या अनेक देशों के रूप में भारत छोड़ने वाले थे, लेकिन बंटवारा अगस्त 1947 में हुआ। लार्ड एटली की ओर से तय की गई तारीख से कम से कम दस महीने पहले। जब मैंने लार्ड माउंटबेटन से यह पूछा था कि बंटवारे को जून 1948 के पहले क्यों लागू कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं देश को इकट्ठा नहीं रख पाया। हालांकि उन्होंने यह कहकर इसे उचित ठहराया कि कोई दूसरा चारा नहीं था।

दरअसल जैसी घटनाएं घटीं वे अमित शाह के विचारों के विपरीत थीं। मैंने जब लार्ड माउंटबेटन से कहा कि बंटवारे के दौरान हुई मौतों के लिए वह जिम्मेदार हैं तो उनका कहना था कि उन्होंने तब 20 लाख लोगों की जान बचाई जब उन्होंने दक्षिण एशिया में अपने सैनिकों के लिए जा रहे अनाज के जहाजों को भारत की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वह इस बात के लिए ईश्वर के सामने कसम खाएंगे कि उन्होंने लोगों को भूख से मरने से बचाया। अमित शाह की टिप्पणी में निराशा का अंश था, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी पार्टी ने सीख ली है। वह एक तरह हिंदुत्व का शासन थोपना चाहती है, इसके बावजूद कि 17 करोड़ मुसलमान उसके खिलाफ हैं। एक बात और जो अमित शाह और उनकी पार्टी को याद रखनी चाहिए कि भारत के पास एक सेक्युलर संविधान है और जो भी देश में शासन करता है उसे इसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा लगता नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को चारों ओर फैला रहा है और इस प्रक्रिया में दूसरों की पहचान मिटा रहा है। भाजपा को उसकी जरूरत है, क्योंकि उसके पास अपना काडर नहीं है। जो भी वजह हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शासन अशुभ है।

(लेखक प्रख्यात पत्रकार एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

नई तरह की राजनीति का नया विस्तार

राजीव सचान

कल्पना करें कोई केजरीवाल की तरह ममता के घर-दफ्तर के भीतर तो दूर रहा, बाहर भी धरना दे तो उसका क्या हश्र होगा?

कहना कठिन है कि काल खंड के किस दौर में राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष एक-दूसरे के पर्याय बन गए? इसी तरह यह जानना भी कठिन है कि कब राजनीति सकारात्मकता के लिए कम और नकारात्मकता के लिए अधिक जानी जाने लगी? आज नेताओं और राजनीतिक दलों के प्रत्येक आचार-व्यवहार के बारे में यही कहा जाता है कि वे राजनीति कर रहे हैं। किसी नेता अथवा दल का कृत्य कितना भी नकारात्मक क्यों न हो, वह राजनीति के रूप में ही परिभाषित और रेखांकित होता है। इसी तरह नेताओं और दलों का सकारात्मक रुख-रवैया और कार्य भी राजनीति के तौर पर ही रेखांकित होता है। इस क्रम में यह भी देखने को मिलता है कि नेता या दल विशेष की सकारात्मक पहल अथवा उसका उचित फैसला भी विरोधी दलों की नजर में नकारात्मक ही अधिक होता है। वे उसकी आलोचना-निंदा करने का कोई जरिया निकाल ही लेते हैं। और कुछ नहीं तो यही कह देते हैं कि यह तो महज जुमलेबाजी है। निःसंदेह इसके उलट भी होता है और इसके तहत नेता अथवा दल विशेष के अनुचित कृत्य की भी सराहना की जाती है। पिछले दिनों ऐसा ही तब हुआ जब चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय में धरना दे रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति न केवल अपना समर्थन व्यक्त किया, बल्कि उसे प्रचारित करने के लिए केजरीवाल के घर भी गए। इन चारों मुख्यमंत्रियों-ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, पिनरई विजयन और एचडी कुमारस्वामी ने यह जानते हुए भी केजरीवाल से मिलने की जिद पकड़ी कि वह राजनिवास यानी उपराज्यपाल के घर-दफ्तर के भीतर बिना अनुमति धरना दे रहे हैं। इन मुख्यमंत्रियों ने न केवल केजरीवाल के धरने को उचित बताया, बल्कि केंद्र सरकार को यह उपदेश भी दिया कि उसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का धरना खत्म कराने की पहल करनी चाहिए।

माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल के प्रति समर्थन प्रकट करने की पहल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुआई में हुई। चारों मुख्यमंत्रियों ने केजरीवाल के धरने के लिए केंद्र सरकार को कोसने का काम नीति आयोग की बैठक में भी किया। उनकी ओर से यह भी संकेत दिए गए कि वे गैर कांग्रेसी दलों की एकजुटता की भी संभावनाएं टटोल रहे हैं। हास्यास्पद यह है कि ऐसा संकेत देने वालों में एचडी कुमारस्वामी भी शामिल थे जो कांग्रेस के समर्थन से ही कर्नाटक में सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये चारों मुख्यमंत्री इससे भली तरह परिचित थे कि कांग्रेस केजरीवाल के धरने को नाटक-नौटंकी बता रही है, फिर भी उन्होंने भाजपा के साथ कांग्रेस को भी एक संदेश देने का काम किया। कोई नहीं जानता कि यह संदेश क्या रहा होगा, क्योंकि केजरीवाल का राजनिवास में घुसकर धरना देना हर लिहाज से एक अशोभनीय कृत्य था। राजनिवास में केजरीवाल के धरने का समर्थन तो वही मुख्यमंत्री कर सकता है जो अपने घर-दफ्तर में असंतुष्ट लोगों को धरना देने की इजाजत देने के लिए तैयार हो? क्या ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, पिनरई विजयन अथवा एचडी कुमारस्वामी यह पसंद करेंगे कि कोई बिना उनकी अनुमति के केजरीवाल की तरह उनके घर-दफ्तर पर धरना देने बैठ जाए? कल्पना करें कि विरोधी दल का कोई नेता अथवा अन्य कोई व्यक्ति ममता बनर्जी या फिर पिनरई विजयन के घर-दफ्तर के भीतर तो दूर रहा, बाहर भी धरना देने की कोशिश करे तो उसका क्या हश्र होगा? ऐसी कल्पना चंद्रबाबू नायडू और एचडी कुमारस्वामी को लेकर भी की जा सकती है, लेकिन जैसी राजनीतिक हिंसा केरल और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है वैसी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नहीं है।

यदि कोई यह जानना चाहे कि चार राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के अराजक धरने को समर्थन देने के लिए आगे क्यों आए तो इसका आम जवाब यही होगा कि राजनीति के चलते, लेकिन आखिर किसी के घर-दफ्तर में घुसकर वहां धरने पर बैठ जाने की हरकत को सही बताना राजनीति कैसे हो सकती है? ऐसे कृत्य को राजनीति कहना ही हो तो वह क्षुद्र, खराब और घटिया राजनीति ही कहा जा सकता है। अपने देश की एक बड़ी विडंबना यह है कि अराजक, अशोभनीय, अमर्यादित और घोर अनुचित कार्यों पर भी राजनीति का आवरण डाल दिया जाता है। परिणाम यह है कि नेता और राजनीतिक दल राजनीति करने के नाम पर हर तरह के अनुचित-अशोभनीय कृत्य करने को तैयार रहते हैं। क्या राजनीति करने के नाम पर नेताओं और दलों को कुछ भी करने की छूट मिली हुई है? निःसंदेह ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीति के नाम पर तमाम बुरे काम इसलिए होने लगे हैं, क्योंकि ऐसे कामों को क्षुद्र राजनीति या कुराजनीति अथवा खराब राजनीति के तौर पर नहीं जाना जाता। यदि राजनीति का कोई विलोम शब्द भी प्रचलन में होता या फिर अनुचित-अनैतिक कार्यों के लिए कुराजनीति जैसा कोई शब्द इस्तेमाल हो रहा होता तो शायद राजनीतिक दल अशोभनीय अनुचित काम करने के पहले कुछ सोच-विचार करते। चूंकि ऐसा कुछ नहीं है इसलिए जिस दल या नेता को जो मन में आता है वह करता है और उसे राजनीति का नाम दे देता है। दुर्भाग्य से एक बड़ी हद तक मीडिया भी यही करता है। शायद यही कारण है कि राजनीति में सही-गलत के बीच की विभाजन रेखा धुंधली होती जा रही है।

आखिरकार केजरीवाल ने नौ दिन बाद अपना धरना समाप्त कर दिया, लेकिन किसी को भी इस फेर में नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि उन्हें अच्छी और बुरी राजनीति का फर्क मालूम चल गया। अगर दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें फटकार नहीं लगाई होती तो शायद वह राजनिवास के सोफे पर कुछ दिन और व्यतीत करते। इस पर भी हैरत नहीं कि उनके समर्थक इसे ही नई तरह की राजनीति की संज्ञा देते। अपने अधिकारियों के आचरण को लेकर केजरीवाल की नाराजगी जायज हो सकती है, लेकिन उनकी ओर से राजनिवास के भीतर घुसकर धरना देने को राजनीति नहीं कहा जा सकता। यह देखना दयनीय रहा कि तथाकथित नई तरह की राजनीति करने निकले और युवा नेता कहे जाने वाले केजरीवाल के अराजक धरने का कई युवा नेताओं ने भी समर्थन किया। इनमें तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी हैं। तेजस्वी यादव अभी राजनीति में नए हैं, लेकिन अखिलेश तो पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। क्या बतौर मुख्यमंत्री उन्हें यह स्वीकार होता कि कोई उनके घर-दफ्तर के भीतर आकर धरने पर बैठ जाता? यह सवाल इसलिए खास तौर पर, क्योंकि उन्हें अपने सरकारी बंगले से इतना लगाव था कि वह उसकी तमाम सामग्री उखाड़ कर ले गए।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आस्था

आस्था के फूल हृदय की पवित्रता रूपी क्यारी में उगे मनोहारी पौधे पर ही खिल सकते हैं। वही आस्था लक्ष्य को पाने में समर्थ हो सकती है, जिसकी जड़ें मौलिकता की खाद से उर्वरा शक्ति पाती हैं। मन के मैलेपन से विकसित और पनपी प्रवृत्ति व्यक्ति को किसी भी मुकाम पर छोड़ देने के लिए विवश हो सकती है। आस्था भक्ति, प्रेम, अपनत्व व आनंद की आधारशिला है। आस्था के पवित्र सरोवर में खिले भावकमल ही प्रभुकृपा का उत्तम प्रसाद पाने के एकमात्र अधिकारी हैं। आस्था की दृढ़ता अपने और अपने आराध्य के मध्य मिलन की दूरी व खाई को पाट देती है।

पक्के और दृढ़ इरादों से विरचित आस्था के मंसूबे धारक को उसकी मनोकामनाओं की अंतिम मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी देते हैं। आस्था अपने साथ विश्वास, नैतिकता, मूल्य व जीवटता को लेकर चलती है। आस्था भटकते राहगीरों और जीवन-सागर में दिशाहीन होकर क्रूर समय के थपेड़े खाते मानव व जीव समुदाय को सही राह दिखाती है। सच तो यह है कि आस्था के बगैर कोई भी व्यक्ति जीवन लक्ष्य में आनंद व खुशी पाने की कल्पना नहीं कर सकता। आस्था सतोगुणी मूल्यवान सृष्टि की रचना करती है, जिसका उद्देश्य विशुद्ध रूप से आराधना में पवित्रता के साथ-साथ जीवन को एक उत्तम उद्देश्य के लिए प्रेरित करना होता है। आस्था की प्रबलता प्रभु की अपने प्रति करुणा और प्रीति के बढ़ने की द्योतक होती है।

उत्साह भी आस्था का ही आत्मजा है जो इससे प्रेरणा पाकर प्रभु मिलन व उनके साक्षात्कार में सहायक होता है। आस्था, पवित्र भावों की वह मंदाकिनी है जिसमें स्नान करने की लिए देवगण स्वयं ही उत्कंठित रहते हैं। आस्था ही भक्ति व भक्त का कवच है। पावन आस्था की ही परिणति है कि प्रभु राम व माता सीता सदैव अपने भक्त पवनपुत्र हनुमान के हृदय में ही विराजमान रहते हैं। आस्था भक्त के पास ईश्वरीय अनुकंपा की अमोघ शक्ति है, जिससे वह किसी भी पावन जीवन-लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकता है। जीवन के अनमोल वैभवों को पाने और आत्मिक व असली आनंद प्राप्ति का मूल मंत्र आस्था है। समृद्धि, खुशहाली, भौतिक, आध्यात्मिक उन्नति और आनंद की जीवन-डोर है आस्था। आओ इसे अपनाकर इस मानव जीवन को सफल और अनुकरणीय बनाएं।

डॉ. दिनेश चमोला 'शैलेश'

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

इतिहास और राजनीति का घालमेल

डॉ. विजय अग्रवाल ने अपने आलेख 'इतिहास की मर्यादा रेखा' के माध्यम से ऐतिहासिक मर्यादा का जो संवेदनशील मुद्दा उठाया है, वह भारतीय राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस सरकार के सहयोगी वामपंथी इतिहासकारों ने भारतवर्ष के इतिहास और उससे जुड़ी प्राचीन संस्कृति को भले ही अपनी वैचारिकी के अनुरूप निरूपित किया हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने इतिहास लेखन में कांग्रेस शासन की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण राजनीति को सुदृढ़ करने के लिए विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी और बाबर की विजयगाथा को महिमामंडित कर भारतीय हिंदू शासकों की वीरतापूर्ण पराजय को उनकी कमजोरी के रूप में उल्लिखित किया है, वह इतिहास का राजनीति के लिए दुरुपयोग करने का अप्रतिम उदाहरण है। इतिहास एक निर्मम सत्य है, जो एक पक्ष के लिए अपमानजनक और दूसरे पक्ष के लिए गौरवपूर्ण हो सकता है, इस ऐतिहासिक सत्य को राजनीतिक लाभ-हानि की दृष्टि से निरूपित कर जन-मानस में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी जाय तो यह इतिहास के साथ क्रूर मजाक है, जो स्वतंत्र भारत में मुगल शासक अकबर को 'महान' और क्रूर औरंगजेब को 'जिंदा पीर' बताकर किया गया है। इस इतिहास लेखन ने एक वर्ग विशेष को तुष्ट और संपुष्ट कर भारत की बहुलतावादी उदार सांस्कृतिक चेतना को दबाने का काम किया है।

pandeyvp1960@gmail.com

भाईचारे में खलल

हम हमेशा से आतंकवाद को धर्म से अलग करते आए हैं। हम कहते आए हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन हमारे नेताओं को यह चीजें समझ में नहीं आती हैं। कभी उन्हें हिंदू आतंकवाद नजर आता है और कभी मुस्लिम आतंकवाद। आखिर कब वह इन तुष्टिकरण की राजनीति से आगे निकल कर आतंकवाद की भयावहता को समझ पाएंगे? इन नेताओं को बयानबाजी से जो भी फायदा मिलता हो लेकिन देश के एक समुदाय एक धर्म आहत होता है और अक्सर यह चीजें चुनाव के समय ही होती हैं नेता वोट की तुष्टिकरण की राजनीति में यही काम करते हैं चुनाव जैसे ही आते हैं तो इस तरह के आरोपों का सिलसिला चल पड़ता है। कभी किसी को आतंकवादी कह देते हैं और कभी किसी धर्म को आतंकवादी बता देते हैं लेकिन जैसे ही यह चीजें अदालत में स्पष्ट होती हैं तो फिर यह दिखावटी माफी मांगने में भी पीछे नहीं रहते। ये नेता आखिर कब समझेंगे।

नीरज झा, दिल्ली विश्वविद्यालय

पेड़-पौधों के रक्षक !

पेड़-पौधे हम सब के जीवन का आधार हैं। प्रति वर्ष बरसात के दिनों में लाखों पौधे लगाने के बड़े दावे किए जाते हैं मगर असल में कितने बच पाते हैं देखने की बात है। इनके उचित संरक्षण और पोषण के बिना ये जल्द सूख जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं जिसमे अमूल्य समय, धन और ऊर्जा की बर्बादी है। देखने को आज पर्यावरण पर बड़ी गोष्ठियां और सभाएं होती हैं मगर दुर्भाग्य से इनके लिए कोई ठोस प्रोग्राम नहीं है। बिना देखे सडकों के साथ पौधे लगा दिए मगर इनके ऊपर से निजली की लाइनें होने से इन्हें काटना ही पड़ता है इससे बर्बादी अलग है। यही नहीं पीपल के पेड़ों को हर वर्ष भेड़-बकरियों वाले बुरी तरह काट डालते हैं जिसे कोई रोकने वाला नहीं है जबकि एक पत्ता भी अमूल्य है। इसलिए अब इनके संरक्षण और पोषण के लिए काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इसी तरह जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए नदियों, नालों और नहरों की सफाई में बड़े रोजगार से राष्ट्र को और आगे लाया जा सकता है। मगर सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है।

vedmamurpur@gmail.com

धरने पर धरना

3 साल बाद एक बार फिर से दिल्ली के सातवें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने धरने प्रदर्शन से विवादों में चर्चित हैं। करीब 3 साल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह धरना दिल्ली वालों के लिए एक बड़ा बदलाव ला पाएगा। क्योंकि एक तरफ अधिकारी दावा कर रहे हैं कि वह हड़ताल पर नहीं है वे रोज दफ्तर जाकर अपना, जनता से जुड़ा काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री का ये धरना और विरोध बेवजह का विवाद खड़ा करना है। इस हड़ताल से दिल्ली वालों के कई कार्य प्रभावित हुए हैं जैसे डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोगों से निपटने की तैयारी नहीं हो पाई। प्रदूषण को मात देने की तैयारी बीच में ही रह गई। उधर मानसून भी आने वाला है। वास्तविकता यह तो नहीं कि आप सरकार यह सब कार्य तय समय के भीतर पूर्ण नहीं कर पाई और इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री यह पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कब जागेंगे। क्या उन्हें ज्ञात नहीं है कि दिल्ली के आधे से ज्यादा नगरों में पानी नहीं आने से त्राहि त्राहि मच रही है। केजरीवाल सरकार का साथ देने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत चार राज्य के मुख्यमंत्री केजरीवाल आवास पर पहुंचे उनका मानना यह है कि दिल्ली में लोकतंत्र खतरे में है इसी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को ज्ञात करना चाहिए कि उनके राज्य में लोकतंत्र की क्या स्थिति है उनको यह सुझाव लेने की आवश्यकता है कि पहले वे अपने राज्य की स्थिति नियंत्रण रख लें फिर किसी और राज्य में जाकर सलाह दें।

neharaow9w{@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

भाजपा-पीडीपी गठबंधन टूटकर अच्छा ही हुआ। वहां हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं और कुछ ठोस होता नहीं दिख रहा है। अब कश्मीर पर नए सिरे से विचार कर वहां हालात दुरुस्त करने के उपायों पर गौर किया जाए।

चेतन भगत@chetan_bhagat

भाजपा-पीडीपी का अलगाव तो होना ही था। वैचारिक रूप से विपरीत ध्रुवों वाली पार्टियों का तीन साल साथ में रहना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। चलो देर आए, दुरुस्त आए।

जफर सरेशवाला@zafarsareshwala

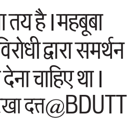

वे खुलकर यह नहीं कह सकते, लेकिन तमाम कश्मीरी राज्य में राज्यपाल शासन चाहते हैं। उनकी जिंदगी पहले ही जहन्नुम बन चुकी है जिसे वे और बदहाल नहीं बनाना चाहते हैं।

राहुल पंडिता@rahulpandita

जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लगना तय है। महबूबा मुफ्ती शायद सोच रही होंगी कि वैचारिक विरोधी द्वारा समर्थन वापसी के बजाय उन्हें पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था।

बरखा दत्त@BDUTT

पीडीपी से समर्थन वापसी के साथ ही भाजपा ने एक तरह से 2019 के आम चुनाव की रणभेरी बजा दी है। अब आप राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और कट्टरता से भरी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाइए।

ऋचा सिंह@richa_singh

जनपथ

बीजेपी ने कह दिया आज तलाक-तलाक,
आतंकी दल को करें अब दिल खोल हलाक।
अब दिल खोल हलाक पाक को सबक सिखाएं,
तभी भरोसा आप गया जो फिर से पाएं।
चलती थी सरकार हुर्रियत की बन जेबी,
सही देर से किंतु चलो जागी बीजेपी!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। **वर्ष 28 अंक 336**